



उदयपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ एवं अनोखी काली गिलहरी दिखाई दी हैं। नेचर एक्टिविस्ट मुकेश पंवार ने इस गिलहरी की तस्वीरें ली हैं। उन्होंने बताया कि, राजस्थान में इस तरह की गिलहरी मिलने की यह पहली घटना है।

उदयपुर संभाग के सागवाड़ा में दिखी काली गिलहरी

वागड़ नेचर क्लब के तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार ने गिलहरी की तस्वीरें ली हैं

उदयपुर, 29 अगस्त (का.सं.)। उदयपुर संभाग के सागवाड़ा शहर के समीप दुर्लभ काली गिलहरी दिखाई दी है। राजस्थान में अपनी तरह की ऐसी पहली काली गिलहरी को खोजने, क्लिक करने और पृष्ठ करने का श्रेय वागड़ नेचर क्लब के सदस्य ख्यातनाम तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार को जाता है।

पंवार ने बताया कि मैलानिस्टिक गिलहरी अक्सर मिलती है लेकिन एकदम गहरी काली गिलहरी मिलना बेहद दुर्लभ होता है। उन्होंने कहा इस गिलहरी के रोएं, आंखें, पूंछ सब काला है। ज्ञातव्य है कि शहर के दो अलग-अलग स्थानों पर काली गिलहरी देखी है। पहले तो लगा कि यह गिलहरी जैसा कोई अन्य जीव है पर चार दिन तक उसके व्यवहार को देखा तो यकीन हो

यह असल में सामान्य गिलहरी है, जो दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति "मैलनिज्म" से ग्रस्त है, जिसमें त्वचा व फर में ब्लैक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण यह गिलहरी काले रंग की है।

इससे पहले उदयपुर संभाग में "ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर" देखा गया था। यह भी एक आनुवंशिक स्थिति है इसमें त्वचा व फर में पिगमेंट नहीं होता है।

गया कि यह गिलहरी है। इस मादा गिलहरी के दो बच्चे भी हैं जो सामान्य हैं। सर्प विशेषज्ञ धर्मेन्द्र व्यास ने बताया कि सामान्यतया समस्त जीवों की त्वचा का रंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित रहता है परन्तु लाखों में एक जीव मैलानिस्टिक (गहरे या काले रंग) में हो सकता है। इसमें त्वचा में या

भावसार, विनय दवे सहित अन्य सदस्यों सहित संभागाभर के प्रकृति व पर्यावरण विशेषज्ञों ने खुशी जताई है। प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. सतीश शर्मा ने बताया कि राजस्थान में काली गिलहरी की साईंटिंग का कोई आधिकारिक रिकार्ड उल्लब्ध नहीं है, संभवतः राजस्थान का यह पहला मामला है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता के कारण वागड़-मेवाड़ अंचल दुर्लभ प्रजातियों के जीवों के लिए बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। हाल ही में यहां ल्यूसिस्टिक किंग फिशर भी दिखा था। इस तरह का किंग फिशर विश्व में तीन बार ही दिखा है। उनमें से एक उदयपुर है। यह भी एक तरह की आनुवंशिक स्थिति है इसमें त्वचा, फर आदि में मैलनिन पिगमेंट का अभाव होता है।

पौडरिक पार्क से पार्किंग प्रोजैक्ट वापस लिया सरकार ने

जयपुर, 29 अगस्त (का.सं.)। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि शहर के पौडरिक पार्क में बनाए जा रहे पार्किंग प्रोजैक्ट को वापस ले लिया गया है। अब पार्क में पार्किंग के नाम पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा।

सरकार ने यह भी बताया कि, पार्किंग के लिए अन्य उचित स्थान की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार के प्राथमिक पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भावनाजी ने पौडरिक पार्क विकास समिति व पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक सहित अन्य की जनहित

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि, पौडरिक पार्क से पार्किंग प्रोजैक्ट वापस ले लिया गया है।

हाई कोर्ट में पार्किंग प्रोजैक्ट के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिन्हें अब निस्तारित कर दिया गया है।

याचिकाओं को निस्तारित किया।

जनहित याचिका में कहा गया था कि, पौडरिक पार्क शहर की विरासत है और आमजन की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मपुरी विहारोपरी क्षेत्र है और वहां पर किसी पार्किंग जगह की जरूरत ही नहीं है। लोगों का पार्क की जमीन पर अधिकार है। यदि नगर निगम को पार्किंग बनानी भी है तो पास के नाले के ऊपर बनाई जा सकती है। पूर्व महापौर ने इस पार्क को किड्स जोन बनाने के लिए कहा था, लेकिन अब मौजूदा राज्य सरकार ने वह प्लान ही बदल दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट कई मामलों में कह चुके हैं कि पार्क व ओपन स्पेस के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि सरकार ने पार्क या ओपन स्पेस के मौजूदा स्वरूप में बदलाव भी कर दिया है तो उसे वापस पुरानी स्थिति में ही लाना होगा। ऐसे में

राज्य सरकार और नगर निगम को पौडरिक पार्क में पार्किंग निर्माण की मंजूरी नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि, राज्य सरकार ने मार्च 2021 में हाइकोर्ट को बताया था की, पार्किंग प्रोजैक्ट का निर्माण रोक दिया गया है और आगामी सुनवाई तक निर्माण नहीं किया जाएगा।

राफेल डील...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को कहा कि "कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई केस नहीं बनता है।" ज्ञातव्य है शर्मा हर मुद्दे पर याचिका दायर करने के आदी है। अपनी याचिका स्वीकार करने के लिए कोर्ट को प्रभावित करने के लिए शर्मा ने कहा, "एक दिन आया जब हरेक व्यक्ति बेबस महसूस करेगा और

"भेड़िया आया, ..."

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्तमान बाद से गहरी आर्थिक क्षति होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन की फण्डिंग वाले वेब्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) के अन्तर्गत नए बने नए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन यदि व्यापक विचिन्स पर गौर किया जाए तो इनका बचना भी मुश्किल है। निर्मित हो चुके गारगंतुआन बी.आर.आई. प्रोजैक्ट्स की पुनर्भूतना जवाबदेहियों को लेकर पाकिस्तान पहले से ही जबरदस्त दबाव में है। इनमें कई प्रोजैक्ट्स सफेद हाथी हैं जो अपने ऋणों की अदायगी करने लायक प्रॉफिट भी नहीं कमा सकें। अब जबकि वे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बाढ़ से तबाह हो चुकी है तो देश पर अलाभकारी एवं अनुपयोगी प्रोजैक्ट्स का भार और आ जाएगा। वे पाकिस्तान के बजट और सार्वजनिक वित्त को भी प्रभावित कर सकता है। फिर भी, शाहबाज शरीफ सरकार पर पानी में फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री लाने का दबाव है। बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों में भोजन को लेकर आपाधापी मची है। बच्चे भी भोजन और पीने के पानी से महरूम हैं। पानी के तेज बहाव से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसलिए जब पानी उतार पर आना शुरू होगा तब उन उच्च स्थलों पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी जहां लोगों ने शरण ले रखी है। बिल्कुल पड़ोस में स्थित भारत इस संकटग्रस्त देश को अहम राहत पहुंचा सकता है, लेकिन राहत देने के लिए भारतीयों का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना होगा जिसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय पसंद नहीं करेगा। भारत सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वह राहत सामग्री को पाकिस्तानी अधिकारियों के सुपुर्द कर दे और उम्मीद करे कि यह पीड़ित जनता के पास पहुंचे जाए।

कोई भी भ्रष्टाचार पर सवाल करने के लिए कोर्ट नहीं आएगा।

सी.जे.आई. ने शर्मा से कहा कोर्ट याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है। बाद में शर्मा याचिका वापस लेने के लिए मान गए जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें अनुमति भी दे दी। शर्मा ने कहा कि वे इस मामले में सी.जी.आई. के पास जाएंगे। कोर्ट ने कहा "आपको कोई भी नहीं रोक रहा

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया गया था। उस समय, चिदम्बरम जिले के इस प्राचीन एवं प्रख्यात मंदिर के पुजारी समुदाय (ब्राह्मण) के बचाव के लिये, अग्रमलाई तुरन्त आगे आ गये थे। सुब्रमन्यम स्वामी, जो तमिलनाडु के निवासी हैं तथा स्वयं को हिन्दू-अधिकांशों के प्रबल हिमायती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ने अपनी इस ताजा मुहिम के जरिये, मन्दिरों की सरकार के नियन्त्रण से बाहर रखने की लड़ाई को अब अपने हाथों में ले लिया है। जहाँ तक दूसरे मुद्दे-गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति का प्रश्न है, इसे मद्रास उच्च न्यायालय करीब-करीब तय कर ही चुका है। न्यायालय ने पुजारियों की नियुक्ति के लिये कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्तें तय कर दी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने, जहाँ गैर-ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किये जाने के सरकारी निर्णय पर रोक लगा दी है, वहीं अदालत ने सरकार को

उन मन्दिरों में पुजारी नियुक्त किये जाने पर भी रोक लगा दी है, जिन मन्दिरों का निर्माण "आमा शास्त्रों" के अनुसार हुआ है। उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि सरकार राज्य के अन्य सभी मन्दिरों में किसी भी जाति के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। लेकिन राजनैतिक विषयको सुभन्त सी.रमन. का मानना है कि मन्दिर और धर्म से सम्बन्धित इस प्रकार के मुद्दों, जो ब्राह्मण समुदाय के पक्ष में दिखाई देते हैं, को उठाने से भाजपा को कोई मदद मिलने की कोई खास सम्भावना नहीं है।

इन्ही विचारों को दोहराते हुये, मद्रास विश्वविद्यालय के प्रो. रामू मणिवन्नन का कहना है कि वस्तुतः इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर, भाजपा डी.एम.के. को राजनैतिक लाभ पहुंचा रही है। अब, सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर, भाजपा तथा उसके समर्थकों ने, एक समुदाय विशेष का पक्ष लेकर,

इस बहस को जीवित रखा है तथा इससे तमिलनाडु में पार्टी को कोई मदद नहीं मिलने वाली है क्योंकि वहाँ ब्राह्मण बहुत कम संख्या में हैं।

प्रो. मणिवन्नन ने आगे कहा, "इसने (भाजपा) ने इस बहस को जीवित रखा है तथा इस प्रकार इसने डी.एम.के. को एक अवसर दे दिया है कि वह सभी समुदायों के लोगों को पुजारी बनाने के अपने प्रयासों को और तेज कर सके क्योंकि ऐसा किया जाना उसकी विचारधारा से तो मेल खाता ही है, उसके वोट बैंक को भी माफिक आता है।"

'गुलाम नबी...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उन्हें अंधाधुंध तरीके से इस्तेव्यु देकर पार्टी को बदनाम करने का काम दिया गया है, जिससे वो अपने आप को और नीचे गिरा रहे हैं।"

प्रदेश में कांग्रेस के 3 अग्रिम संगठन हुए बेघर, सामान रखने की भी जगह नहीं

जिन भवनों में इनके मुख्यालय थे, उन्हें खाली करवा लिया गया है

- अस्पताल रोड स्थित जिस बंगले को प्रदेश मुख्यालय बनाया जाना था, वह अब बनेगा वॉर रूम।
- राजस्थान में, 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से पार्टी का नया प्रदेश मुख्यालय बनाए जाने की बात हो रही है, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

मुख्यालय बनाया गया तो भीड़भाड़ के चक्कर में यहां कई एंग्लोस फंसेगी और यदि कोई अनहोनी हो गई तो वह कांग्रेस के सिर आएगी। ऐसे में यहां कांग्रेस मुख्यालय बनाने के विचार को स्थगित कर दिया गया। लेकिन तय किया गया कि अस्पताल रोड वाले बंगले में वॉर रूम बनाया जाएगा।

यह बंगला कांग्रेस ने अपने नाम आवंटित करवा लिया था। सवाई जयसिंह हाईवे स्थित सरकारी बंगला जिसमें कि पिछले 30 से ज्यादा सालों से कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्यालय चल रहे थे, उसे खाली किया जाना भी जरूरी था। ऐसे में सोमवार को तीनों अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते रहे।

मजेदार बात यह है कि वर्ष 1998 के बाद से अशोक गहलोत सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो प्रदेश कांग्रेस खुद के लिए नया मुख्यालय और ना ही अपने

कार्यालयों का फर्नीचर और अन्य सामग्री आखिरकार कहां रखी जाए। तीनों संगठनों के अध्यक्षों ने इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस से चर्चा की तो प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें बैठने के लिए स्थान देने में चार-पांच दिन का समय लग जाएगा। वे सामान रखने की व्यवस्था अपने स्तर पर कर ले, लेकिन यह व्यवस्था सोमवार दोपहर बाद तक नहीं हो पाई। अतः ऐसे में थोड़ा बहुत सामान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रखवाया गया। वहीं कागजात तीनों अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते रहे।

मजेदार बात यह है कि वर्ष 1998 के बाद से अशोक गहलोत सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो प्रदेश कांग्रेस खुद के लिए नया मुख्यालय और ना ही अपने

अग्रिम संगठनों के लिए कोई स्थान चिन्हित कर पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के लिए मानसरोवर में स्थान चिन्हित किया गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब बीच शहर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मानसरोवर में कितने लोग पहुंचेंगे, क्योंकि वह स्थान शहरी क्षेत्र से बहुत दूर है।

इसके बाद तय किया गया कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही तीनों अग्रिम संगठनों को कमरे आवंटित किए जाएंगे, लेकिन यहां भी समस्या यह है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कमरों की संख्या सीमित है। ऐसे में यदि इन तीनों अग्रिम संगठनों को कमरे आवंटित भी कर दिए जाते हैं, तो बैठने की जगह नहीं बचेगी। खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी ना तो प्रदेश कांग्रेस के पास अपना खुद का बड़ा मुख्यालय बनाने की जमीन तय की गई और अब जब अग्रिम संगठनों से मुख्यालय खाली करवा लिया गया है, तो उनके लिए भी स्थान की कोई व्यवस्था नहीं है।

तमिलनाडू में मंदिरों के मैनेजमेंट पर काबिज...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया गया था। उस समय, चिदम्बरम जिले के इस प्राचीन एवं प्रख्यात मंदिर के पुजारी समुदाय (ब्राह्मण) के बचाव के लिये, अग्रमलाई तुरन्त आगे आ गये थे। सुब्रमन्यम स्वामी, जो तमिलनाडु के निवासी हैं तथा स्वयं को हिन्दू-अधिकांशों के प्रबल हिमायती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ने अपनी इस ताजा मुहिम के जरिये, मन्दिरों की सरकार के नियन्त्रण से बाहर रखने की लड़ाई को अब अपने हाथों में ले लिया है। जहाँ तक दूसरे मुद्दे-गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति का प्रश्न है, इसे मद्रास उच्च न्यायालय करीब-करीब तय कर ही चुका है। न्यायालय ने पुजारियों की नियुक्ति के लिये कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्तें तय कर दी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने, जहाँ गैर-ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किये जाने के सरकारी निर्णय पर रोक लगा दी है, वहीं अदालत ने सरकार को

उन मन्दिरों में पुजारी नियुक्त किये जाने पर भी रोक लगा दी है, जिन मन्दिरों का निर्माण "आमा शास्त्रों" के अनुसार हुआ है। उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि सरकार राज्य के अन्य सभी मन्दिरों में किसी भी जाति के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। लेकिन राजनैतिक विषयको सुभन्त सी.रमन. का मानना है कि मन्दिर और धर्म से सम्बन्धित इस प्रकार के मुद्दों, जो ब्राह्मण समुदाय के पक्ष में दिखाई देते हैं, को उठाने से भाजपा को कोई मदद मिलने की कोई खास सम्भावना नहीं है।

इन्ही विचारों को दोहराते हुये, मद्रास विश्वविद्यालय के प्रो. रामू मणिवन्नन का कहना है कि वस्तुतः इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर, भाजपा डी.एम.के. को राजनैतिक लाभ पहुंचा रही है। अब, सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर, भाजपा तथा उसके समर्थकों ने, एक समुदाय विशेष का पक्ष लेकर,

इस बहस को जीवित रखा है तथा इससे तमिलनाडु में पार्टी को कोई मदद नहीं मिलने वाली है क्योंकि वहाँ ब्राह्मण बहुत कम संख्या में हैं।

प्रो. मणिवन्नन ने आगे कहा, "इसने (भाजपा) ने इस बहस को जीवित रखा है तथा इस प्रकार इसने डी.एम.के. को एक अवसर दे दिया है कि वह सभी समुदायों के लोगों को पुजारी बनाने के अपने प्रयासों को और तेज कर सके क्योंकि ऐसा किया जाना उसकी विचारधारा से तो मेल खाता ही है, उसके वोट बैंक को भी माफिक आता है।"

क्या गुलाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी के पास एक ही तरीका है कि नेशनल कॉंग्रेस को घाटी में एकतरफा जीत दर्ज करने से रोका जाए जहां तक जम्मू क्षेत्र का सवाल है, परिसीमन के बाद भाजपा की स्थिति और सुरक्षित हो गई है क्योंकि नए विधानसभा क्षेत्रों के वोटर भाजपा के पक्ष के प्रतीत होते हैं। जम्मू में हिन्दू भावनाओं का संघार अधिक है, इसलिए आजाद की पार्टी के यहां भाजपा का हितसाधन करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आजाद घाटी में मुस्लिम मतदाताओं को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो इससे भाजपा को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिल सकती है। आजाद जहां "धर्म-निरपेक्ष विचार धारा" का समर्थन करने पर कायम हैं, वहीं यह बात भी गौर करने लायक है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति सोमवार को फिर उत्साहपूर्ण अंदाज में बोला और "मानवीय संवेदनाओं" को लेकर उनकी प्रशंसा की।

मणपुरम गोल्ड लोन कम्पनी में डकैती 12 करोड़ रू. का सोना व 11 लाख रू. नकद लूटा

शहर के सुंदरवास क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई वारदात

- सीसीटीवी कैमरे में पिस्तौल की नॉक पर स्टफ को डराते दिखे लुटेरे।
- दो बाइक पर आए थे पांच लुटेरे।

उदयपुर 29 अगस्त, (नि.सं.)। शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित सुंदरवास क्षेत्र में सोमवार सुबह बाइक पर आए पांच लुटेरे एक बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। क्षेत्र में मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी में घुस इन लुटेरों ने पहले पिस्टल की नॉक पर कर्मचारियों को बंधक बनाया और उसके बाद कंपनी में 12 करोड़ रूपए आंकी गई है वहीं कंपनी में रहे 11 लाख रूपए नकद लूट ले गए। वारदात के बाद पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए संभागभर में नाकेबंदी करवाई लेकिन लुटेरे अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबहे प्रतापनगर थानाक्षेत्र के सुन्दरवास मुख्य मार्ग पर स्थित मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी में घुसते ही नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में मौजूद

एक महिला सहित छः कर्मचारियों को पिस्टल दिखा बंधक बना मारपीट शुरू कर दी। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लुटेरों ने वहां बने लॉकर से करीब चौबीस किलो सोना व ग्यारह लाख रूपये की नकदी लूट ले गए। पांच बदमाश दो बाइक पर सवार होकर चेहरे को नकाब से ढ के हुए वारदात करने पहुंचे थे। कंपनी खुलते ही अंदर घुसे दो इन लुटेरों ने कर्मचारियों को पिस्टल दिखा एक जगह इकट्ठा कर नीचे बिठा दिया तथा उनके हाथ बांध दिए। इस दौरान बदमाशों के शेष साथियों ने आपस की नोक पर लॉकर से नकदी व सोना लेकर

फरार हो गए। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चन्द्रशील ठाकुर ने मय जाता मौके पर पहुंच कर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इस पर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में बैंक कर्मचारियों से घुसटाछ की और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए रेंज में नाकाबंदी करवाई है। पुलिस की विभिन्न टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी है।

गुलाम नबी ने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाने का क्रम...

आजाद के इस्तीफे में राहुल गांधी की एक अत्यन्त तीखी टिप्पणी, उनके द्वारा 2013 में सबसे सामने एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने वाली घटना से संबंधित थी। आजाद ने इस कार्य को उनका बचकाना व्यवहार तथा उनकी अपरिपक्वता का जबरदस्त नमूना बताया था।

आजाद ने कहा, "इस कार्य से प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) तथा पूरे मंत्रिमण्डल के अधिकार एवं गौरव का क्षरण हुआ था। मैं नहीं जानता कि राहुल जी को आज तक भी मालूम है या नहीं कि अध्यादेश कैसे जारी किये जाते हैं। जो चीज सरकार के प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुख के नेतृत्व में पारित हुई है- आप उसे सबके सामने फाड़कर फेंक रहे हैं।"

आजाद ने अपने इस्तीफे में जो यह आरोप लगाया था कि "महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा यहाँ तक कि उनके सिक्वोरिटी गार्ड्स तथा पी.ए. (पर्सनल असिस्टेन्ट्स) द्वारा लिये जाते हैं, इसके

बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है। उन्हें पूजा कि ऐसा नेता किस प्रकार का अध्यक्ष होगा..... कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति जानता है कि वे लोग कौन हैं, जिनके जरिये लोग राहुल गांधी तक पहुँच पाते हैं।" आर.एस.एस. द्वारा लगाये जाने वाले "मदर-सन सिन्ड्रोम" के आरोप का अनुसर्ण करते हुये, आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन वे (सोनिया) उन पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गई हैं।

"सभी माँ ऐसी ही होती है। सभी माँ-मेरी माँ, आपकी माँ- उनके बच्चे उनकी कमजोरी होते हैं।" आजाद ने मीडिया के साथ हुई इस बातचीत में चर्चित घटनाओं या बातों का ही जिक्र किया है। लेकिन राहुल को अपने हमले का निशाना बनाते हुये, वे इस बात को भूल गये कि उन जैसे वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को "पप्पू" के रूप में चित्रित करने के आर.एस.एस.-भाजपा

बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है। उन्हें पूजा कि ऐसा नेता किस प्रकार का अध्यक्ष होगा..... कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति जानता है कि वे लोग कौन हैं, जिनके जरिये लोग राहुल गांधी तक पहुँच पाते हैं।" आर.एस.एस. द्वारा लगाये जाने वाले "मदर-सन सिन्ड्रोम" के आरोप का अनुसर्ण करते हुये, आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन वे (सोनिया) उन पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गई हैं।

"सभी माँ ऐसी ही होती है। सभी माँ-मेरी माँ, आपकी माँ- उनके बच्चे उनकी कमजोरी होते हैं।" आजाद ने मीडिया के साथ हुई इस बातचीत में चर्चित घटनाओं या बातों का ही जिक्र किया है। लेकिन राहुल को अपने हमले का निशाना बनाते हुये, वे इस बात को भूल गये कि उन जैसे वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को "पप्पू" के रूप में चित्रित करने के आर.एस.एस.-भाजपा

बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है। उन्हें पूजा कि ऐसा नेता किस प्रकार का अध्यक्ष होगा..... कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति जानता है कि वे लोग कौन हैं, जिनके जरिये लोग राहुल गांधी तक पहुँच पाते हैं।" आर.एस.एस. द्वारा लगाये जाने वाले "मदर-सन सिन्ड्रोम" के आरोप का अनुसर्ण करते हुये, आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन वे (सोनिया) उन पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गई हैं।

"सभी माँ ऐसी ही होती है। सभी माँ-मेरी माँ, आपकी माँ- उनके बच्चे उनकी कमजोरी होते हैं।" आजाद ने मीडिया के साथ हुई इस बातचीत में चर्चित घटनाओं या बातों का ही जिक्र किया है। लेकिन राहुल को अपने हमले का निशाना बनाते हुये, वे इस बात को भूल गये कि उन जैसे वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को "पप्पू" के रूप में चित्रित करने के आर.एस.एस.-भाजपा